फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 73 संख्याः 261 प्रभात जयपुर, सोमवार 24 अप्रेल , 2023 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 3.50 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

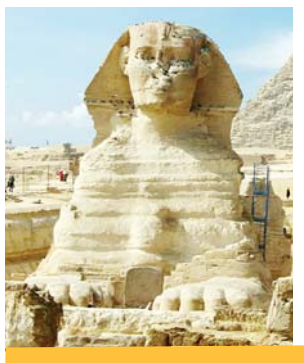

The Sphinx Speaks & Isis Sooths Crocs

According to legend, the Sphinx guarded the entrance to the city of Thebes, and posed a riddle to anyone who wished to enter.

Controlling Feel Good

Trending Earring Styles There's a wide array of earring types to suit your style

पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रविवार को जयपुर के झारखण्ड महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पायलट ने कहा, कि वे भगवान भोलेनाथ से प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद लेने आये हैं।

पायलट ने मु.मंत्री गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा, हमने पटवारी पर छापे मारने के लिए वोट नहीं मांगे थे

'25 सितंबर की घटना कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरोध में बगावत थी, विद्रोह से पार्टी और सरकार को क्षति पहुंची'

- पायलट ने कहा, सोनिया गांधी के आदेशों की अवहेलना हुई, खड़गे और माकन की बेइज्जती हुई, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई।
- रंधावा संजीदा, समझदार व्यक्ति हैं, यह रिपोर्ट भी बनानी चाहिए कि, मंत्री-विधायकों पर आरोप लगे, उसका संज्ञान लेकर खड़गे तक पहुंचाना चाहिए, ताकि कार्रवाई करें।

जयपुर, 23 अप्रेल (का.प्र.)। लंबे समय से अपनी कही हुई बातों की सुनवाई नहीं होने को लेकर इस बार सचिन पायलट ने सीधे-सीधे आलाकमान को चेताया है कि, 25 सितंबर को जो कुछ हुआ, वह सबके सामने है। खुलेआम सोनिया गांधी के आदेशों की अवहेलना हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन की बेइज्जती हुई, लेकिन कारण बताओ नोटिस देने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सचिन पायलट ने अपने अनशन के जरिए भाजपा के समय हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे से अलग इस बार सीधे आलाकमान तक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है कि, राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है, वह सीधे-सीधे आलाकमान को चुनौती देने वाला काम है। इसी के साथ उन्होंने राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी सलाह दी है कि, जिस तरह से राजस्थान के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इस बारे में भी रिपोर्ट बनाकर उन्हें एआईसीसी तक पहुंचानी चाहिए, ताकि कार्यवाही हो सके। कुल मिलाकर सचिन पायलट की ओर से पिछले कुछ दिनों से सीधे टकराव का रास्ता अपना लिया गया है।

वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए रविवार को कहा कि, हमने पटवारी पर छापे मारने के लिए वोट नहीं मांगे थे। अनशन के दो सप्ताह के बाद भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की है, यह अनशन पार्टी के हित में था। गौरतलब है कि, गहलोत ने पायलट के आरोपों पर कहा था कि भ्रष्टाचार पर जितनी कार्रवाई राजस्थान में हुई, उतनी कहीं नहीं हुई। रविवार को झारखंड महादेव मंदिर में सचिन पायलट ने कहा कि, 25 सितंबर को जो कुछ हुआ, वह सबके सामने है। खुलेआम सोनिया गांधी के आदेशों की अवहेलना हुई, खड़गे साहब और माकन की खुलेआम बेइज्जती की गई। पार्टी विरोधी गतिविधि तो वह थी। उसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर थम गई, उस पर भी सवाल उठेंगे, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है। यह बात सच है कि 25 सितंबर की घटना हुई, वह उस समय की हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरोध में बगावत थी। जो विद्रोह हुआ था, उससे पार्टी और सरकार को क्षति पहुंची थी। सब पब्लिक डोमेन है। पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी किया। उसके बाद जवाब आए नहीं आए, क्या कार्रवाई हुई, यह सवाल तो बनता ही है।

इसी के साथ पायलट ने अपने अनशन को लेकर कहा कि कमलनाथ और वेणुगोपाल से बात हुई। उसमें हमने पक्ष रखा, सच्चाई बताई। बैकग्राउंड को बताया। भविष्य में क्या चाहते हैं, किस दिशा में हमारी पार्टी को जाकर जीत मिल सकती है, उसके बारे में उन्हें सुझाव दिया है। वह सुझाव एक ही है कि, हमने जो कहा, वह करके दिखाना चाहिए, क्योंकि हम बीजेपी का धुआं निकालने की क्षमता रखते हैं, वह इस भ्रम को नहीं फैला दें कि यहां किसी तरह की सांठगांठ है।

उन्होंने कहा कि, पब्लिक परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण है, यह परसेप्शन नहीं बने कि मिले हुए हैं, इसलिए मैंने बात को रखा है। उन्होंने कहा कि, वसुंधरा राजे की सरकार में तमाम माफिया पनपा। हम राष्ट्रपति से मिले, ज्ञापन दिया। किसी ने गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए। अनशन के दो हफ्ते बाद भी कोई

(शेष पृष्ठ 7 पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है।
कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
फ्री सुनाई की जाँच
TRIAL OF HEARING AID
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingsolutions.com

खालिस्तान समर्थक अमृतपाल मोगा जिले के एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार हुआ

पंजाब पुलिस को 36 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद यह कामयाबी मिली

- पंजाब पुलिस ने बतया कि, अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने मोगा जिले रोडे गांव को चारों ओर से घेर लिया था।
- अमृतपाल ने एक गुरुद्वारे में शरण ले रखी थी, रविवार सुबह करीब 6.45 बजे उसने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया।

चंडीगढ़, 23 अप्रैल (वार्ता)। पंजाब की अमृतसर पुलिस और इंटैलिजैंस विंग ने एक संयुक्त आरेशन में 'वारिस पंजाब दे' संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक भगोड़े अमृतपाल सिंह को रविवार सुबह रोडे गांव के एक गुरूद्वारे से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) सुखचैन सिंह गिल ने प्रेसवार्ता में बताया कि अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ 36 दिनों तक चले सर्च अभियान के पश्चात आज सुबह पौने सात बजे अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। उन्होने कहा कि खुफिया सूचनाओं के बाद आज सुबह पूरे रोड गांव की घेराबंदी कर दी गई थी। पंजाब पुलिस के विभिन्न विंग सहयोग से काम कर रहे थे। उन्होने कहा कि चूंकि अमृतपाल गुरुद्वारे के अंदर था, इसलिए पुलिस ने इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं किया। उन्होने कहा कि हमारे पास विशेष इनपुट था कि अमृतपाल सिंह रोडे गांव में मौजूद था, उसे घेर लिया गया था और उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था।

आईजीपी गिल ने बताया कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर डिब्रुगढ़ जेल के लिए रवाना कर दिया गया है, जहां अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह सहित उनके नौ अन्य सहयोगी पिछले महीने से ही डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्होने चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होने इस सारे आपरेशन दौरान राज्य में शांति बनाए रखने के लिए लोगों का धन्यवाद किया।

उल्लेखनीय है कि दो दिन पूर्व अमृतपाल की पत्नी किरनदीप कौर को भी लंदन जाने की कोशिश करते समय अमृतसर के हवाई अड्डे पर रोक लिया था जहां लगभग चार घंटे पूछताछ करने उपरांत उसे उसके गांव वापस भेज दिया था।

डिब्रूगढ़ के मोहनबाड़ी हवाई अड्डे पर रविवार सुबह से ही भारी सुरक्षा तैनाती देखी जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को विशेष विमान से एनएसए और पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ लाया जाएगा। असम पुलिस की एक विशेष टीम एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करेगी। इस बीच, डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पहले से ही बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन रविवार को और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए।

पंजाब के सभी पुलिस आयुक्तों और एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि वे शांति सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखें और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कानून व्यवस्था बनाए रखें। कुछ कट्टरपंथी संगठनों द्वारा

(शेष पृष्ठ 7 पर)

सूचना

आज से राष्ट्रदूत जयपुर संस्करण की एक प्रति का मूल्य 3.50 रुपये कर दिया गया है।

-प्रबन्धक

हैलिकॉप्टर की चपेट में आने से उत्तराखण्ड के वरिष्ठ अधिकारी की मौत

देहरादून 23 अप्रैल (वार्ता)। रविवार को केदारनाथ में हैलिकॉप्टर की चपेट में आने से उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (यूकाडा) के वित्त नियंत्रक

- उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (यूकाडा) के वित्त नियंत्रक अमित सैनी की मौत हो गई।

अमित सैनी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि, वे देहरादून में हैलिकॉप्टर राइड से संबंधित सेवाओं एवं सुविधाओं की जांच परख करने पहुँचे थे। अचानक वे

(शेष पृष्ठ 7 पर)

सूडान में फंसे हैं तीन हजार भारतीय

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (वार्ता)। सरकार ने युद्धग्रस्त सूडान में फंसे करीब तीन हजार प्रवासी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना के दो विमान एवं नौसेना के एक युद्धपोत को सूडान के निकट तैनात कर दिया है और ज़मीनी सुरक्षा परिस्थिति में मौका मिलते ही आकस्मिक निकासी अभियान चलाया

- केन्द्र सरकार ने युद्ध ग्रस्त सूडान से प्रवासी भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए मिशन शुरु किया।

जाएगा।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि, भारत सरकार सूडान में जटिल और उभरती सुरक्षा स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बयान में कहा गया, हम उन भारतीयों की सुरक्षित आवाजाही के लिए विभिन्न साझेदारों के साथ भी निकटता से समन्वय कर रहे हैं जो सूडान में फंसे हुए हैं और उन्हें निकालना चाहते हैं।

यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों को धरना फिर शुरु हुआ

पहलवानों का आरोप है कि, ढ़ाई महीने बीत जाने के बाद भी केन्द्र सरकार ने, कोई कार्रवाई नहीं की है

- पहलवान बजरंग पूनिया व साक्षी मलिक इस धरना प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं।
- पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि, हमने दो दिन पहले सी.पी पुलिस थाने में शिकायत की थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
- भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर सात लड़कियों से छेड़छाड़ व यौन उत्पीड़न का आरोप है।

नई दिल्ली, 23 अप्रेल। दिल्ली के जंतर-मंतर पर बजरंग पूनिया सहित कई पहलवानों का फिर से धरना शुरू हो गया है। धरने के बारे में पहलवानों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धरने को लेकर पूरी जानकारी दी गई। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि, हमने दो दिन पहले सी.पी. पुलिस थाने में शिकायत की थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सात लड़कियों ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई है। उनमें से एक लड़की नाबालिग है और यह मामला पॉस्को एक्ट के अंदर आता है। उन्होंने कहा, ढाई महीने हो गए, लेकिन इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा गठित समिति का कोई फैसला नहीं आया है।

साक्षी मलिक ने कहा कि, सैक्सुअल हैरेसमेंट का मामला था। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला है। मामले की सुनवाई नहीं हुई तो हम हारकर वापस यहां आने पर मजबूर हो गए। हमें लोग झूठे समझने लगे हैं। लोगों को लगता है कि, हम झूठ बोल रहे थे। हम अपना करियर, फ्यूचर और परिवार सब दांव पर लगा कर आए हैं, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कौन उनके साथ है, कौन नहीं आप बेहतर जानते हैं। कोई तीन महीना से सब से समय मांग रहे हैं, खेल मंत्री और मंत्रालय से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम खत्म हो गए, इसीलिए मजबूरन धरना दे रहे हैं, लोग

(शेष पृष्ठ 7 पर)

'राजस्थान राइट टू हैल्थ गैर जिम्मेदाराना लोक लुभावन तत्व का प्रतिनिधित्व करता है'

'जनता को ऐसा अधिकार दिया गया है, जिसे अमल में लाने के लिये जरूरी वित्तीय व मानव संसाधन राज्य के पास नहीं हैं'

-डॉ. अरविंद पानगड़िया-

जयपुर, 23 अप्रेल। नीतियों और योजनाओं में लोक-लुभावन तत्व दो प्रकार का होता है- ज़िम्मेदाराना और गैर ज़िम्मेदाराना। ज़िम्मेदार लोक लुभावन तत्व ऐसी नीतियों और योजनाओं को आगे बढ़ाता है जो वोट खींचती हैं और उपलब्ध वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों के अंदर क्रियान्वित होती हैं तथा समग्र सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाती हैं। गैर ज़िम्मेदराना लोकलुभावन तत्व भी वोट खींचने में मदद करता है लेकिन यह लोकलुभावन तत्व ना तो उपलब्ध संसाधनों के अनुरुप होता है, ना ही समाज कल्याण को आगे बढ़ा पाता है।

राजस्थान में राइट टू हैल्थ बिल, 2022

डॉ. अरविन्द पानगड़िया कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं तथा मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं, अतः राज्य की आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक स्थिति से काफी वाकिफ रहते हैं तथा हाल ही में प्रकाशित लेख में राजस्थान राइट टू हैल्थ बिल, 2022, पर उन्होंने सार गर्भित टिप्पणी की है।

इसी प्रकार के गैर ज़िम्मेदाराना लोक लुभावन तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस मामले में समस्या यह है कि जनता को एक ऐसा अधिकार दिया जा रहा है, जिसे अमल में लाने के लिए राज्य के पास जरुरी वित्तीय एवं मानव संसाधन की कमी है। इस संदर्भ में, यह स्मरण दिलाना उल्लेखनीय होगा कि पिछली बार सरकार ने देश में शिक्षा को कानूनी अधिकार देने का लक्ष्य तय किया था जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का कानूनी अधिकार दिया गया था। इस अधिकार को अमल में लाने वाला अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। उस तिथि तक 6 से 14 साल के 96 प्रतिशत बच्चे पहले से ही स्कूल में थे तथा इस प्रकार यह अधिकार प्रदान करना आसान हो गया था परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में स्थिति इस प्रकार की नहीं है।

- इसके अलावा राज्य इस स्थिति में भी नहीं है कि, आगामी वर्षों में राज्य के इन संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि अपेक्षित है।
- वित्त के सतत कुप्रबंधन तथा खराब शासन प्रशासन के चलते, राज्य (राजस्थान) देश के बड़े राज्यों में दूसरा सर्वाधिक ऋण ग्रस्त राज्य बन चुका है तथा राज्य की ऋण की ''सस्टेनबिलिटी'' पर सवाल खड़े होने लगे हैं।
- इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं है कि, राइट टू हैल्थ बिल जिस रूप में पारित हुआ है, अपने क्रियान्वयन का पूरा भार मौजूदा अस्पतालों पर डाल रहा है।

राजस्थान में वर्तमान चिकित्सा संसाधन, राइट टू हैल्थ को कानूनी रुप से अच्छी तरह लागू करने के लिहाज से बहुत ही कम हैं। इसके अलावा, राज्य इस स्थिति में भी नहीं है कि आगामी वर्षों में इन संसाधनों में अपेक्षित एवं उल्लेखनीय वृद्धि एवं विस्तार कर सके। वित्त के सतत कुप्रबंधन तथा खराब शासन प्रशासन के चलते यह राज्य देश के बड़े राज्यों में दूसरा सर्वाधिक ऋण ग्रस्त राज्य बन चुका है। इसे कोढ़ में खाज ही कहा जायेगा कि राज्य के ग्रॉस स्टेट डॉमेस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) के अनुपात में राजकोषीय घाटा इन वर्षों में सर्वोच्च रहा है, जिसके चलते राज्य की ऋण चुकाने की क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली, 23 अप्रेल। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में कथित तौर पर

- दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को लेकर पुलिस को नोटिस जारी किया है।

प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर पुलिस को नोटिस जारी किया है। महिला पहलवानों ने दिल्ली महिला आयोग से शिकायत की है कि, उन्होंने दो दिन पहले पुलिस को लिखित शिकायत दी है,

(शेष पृष्ठ 7 पर)